



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 794]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 21, 2017/भाद्र 30, 1939

No. 794]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 21, 2017/BHADRA 30, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2017

सं. 88/2017-सीमाशुल्क (गै.टै.)

**सा.का.नि. 1177(अ).**—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 75 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियमों को बनाती है, अर्थात् :-

## 1. लघु शीर्षक, सीमा और प्रारंभ -

- (1) ये नियम सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017 कहलाएंगे।
- (2) ये संपूर्ण भारत में लागू होंगे।
- (3) ये नियम 1 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होंगे।

## 2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न हो, -

(क) "प्रतिअदायगी" से तात्पर्य भारत में निर्मित और निर्यातित किसी भी माल के संबंध में, ऐसे माल के निर्माण में इस्तेमाल किसी भी आयातित सामग्री या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के क्रमशः उप-नियम (7) के अंतर्गत उद्बहणीय एकीकृत कर और उप-धारा (9) के अंतर्गत उद्बहणीय प्रतिपूर्ति उपकर के अलावा प्रभार्य शुल्क की छूट है;

(ख) "उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री" से तात्पर्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अंतर्गत उत्पाद शुल्क के अधीन भारत में उत्पादित अथवा विनिर्मित किसी सामग्री से है;

(ग) “निर्यात” से तात्पर्य इसकी व्याकरणिक रूपांतरों और आत्मीय अभिव्यक्तियों के साथ, भारत से भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाने या घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) के किसी स्थान से किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में ले जाने से है और जिसमें किसी विदेशी बंदरगाह को जाने वाले किसी यान अथवा हवाई जहाज पर उपयोग हेतु व्यवस्थाओं अथवा स्टोर अथवा उपकरण के लदान शामिल है ;

(घ) “आयातित सामग्री” से तात्पर्य भारत में आयातित कोई सामग्री और जिस पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत शुल्क प्रभार्य हो, से है ;

(ङ) “निर्माण” में माल का प्रसंस्करण अथवा माल पर किए गए कोई अन्य कार्य शामिल है, और पारिभाषिक शब्द निर्माता का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(च) “कर विजक” से तात्पर्य केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 31 में संदर्भित कर विजक से है ।

### 3. प्रतिअदायगी –

(1) निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन –

(क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम ;

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम; और

(ग) इन नियमों के अनुसार, ऐसी रकम या ऐसी दर पर, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, वस्तुओं के निर्यात हेतु प्रतिअदायगी की अनुमति दी जा सकती है :

बशर्ते कि जहां कोई माल आयातित सामग्रियों या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्रियों से निर्मित है या निर्मित किया जाता है, जिनमें से कुछ पर ही प्रभार्य शुल्क का भुगतान किया गया है और शेष पर भुगतान नहीं किया गया है, या प्रभार्य शुल्क का मात्र एक भाग ही अदा किया गया है; या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधान के अंतर्गत, अदा किये गये शुल्क की पूरी या आंशिक छूट या धनवापसी की गयी है या क्रेडिट दिया गया है, उक्त माल पर स्वीकार्य प्रतिअदायगी को कम शुल्क भुगतान या छूट, धनवापसी या प्राप्त क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए घटाया जाएगा :

बशर्ते और आगे कि किसी प्रतिअदायगी की अनुमति नहीं दी जाएगी –

- (i) यदि मिश्रित चाय के निर्यात के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली चाय की चेस्ट को छोड़कर उक्त माल, निर्माण के बाद उपयोग में लिया गया है;
- (ii) यदि शुल्क भुगतान किए बिना आयातित सामान अथवा उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री, का प्रयोग करते हुए उक्त माल का निर्माण या उत्पादन किया जाता है;
- (iii) निर्यात वस्तुओं अर्थात् जूट (बिमलीपाटम जूट या मेस्ता फाइबर सहित) यार्न, मोड़, सुतली, धागा, तारें और रस्सियां के निर्माण में प्रयोग किया गया जूट बैचिंग तेल पर;
- (iv) यदि उक्त सामान, पैकिंग सामग्री होने के नाते निम्नलिखित के निर्यात में या निर्यात के संबंध में उपयोग किया गया है –

(क) जूट यार्न (बिमलीपाटम जूट या मेस्ता फाइबर सहित), मोड़, सुतली, धागा और रस्सी जिसमें जूट यार्न वजन में प्रबल होता है;

(ख) जूट कपड़े (बिमलीपाटम जूट या मेस्ता फाइबर सहित), जिसमें जूट वजन में प्रबल होता है;

(ग) कहीं और विनिर्दिष्ट नहीं जूट विनिर्माता (बिमलीपाटम जूट या मेस्ता फाइबर सहित) जिसमें जूट वजन में प्रबल होता है ।

(2) इस नियम के अंतर्गत प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण किए जाने में, केंद्र सरकार निम्नलिखित का ध्यान रखेगी, -

(क) प्रत्येक वर्ग या वर्णन की सामग्री की औसत मात्रा या मूल्य का, जिसमें से एक विशेष श्रेणी के सामान का सामान्यतः भारत में उत्पादन या निर्माण किया जाता है;

(ख) माल के किसी विशेष वर्ग के भारत में उत्पादन या निर्माण हेतु प्रयुक्त आयातित सामग्री अथवा उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री की औसत मात्रा या मूल्य;

(ग) सामानों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सेमिस, घटकों और मध्यवर्ती उत्पादों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले आयातित सामग्री या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर अदा किए गए शुल्कों की औसत राशि;

(घ) निर्माण की प्रक्रिया में बर्बाद हुई सामग्री और उत्प्रेरक एजेंटों पर अदा किए गए शुल्कों की औसत राशि:

बशर्ते कि यदि ऐसे किसी कचरे या उत्प्रेरक एजेंट को किसी निर्माण प्रक्रिया में पुनः प्रयोग किया जाता है या उसे बेचा जाता है, तो प्रयुक्त किए या बेचे गए कचरे या उत्प्रेरक एजेंट पर शुल्कों की औसत राशि की भी कटौती की जाएगी;

(ङ.) निर्यात माल की पैकिंग या उन्हें रखे जाने हेतु प्रयुक्त आयातित सामग्री या उत्पाद शुल्क योग्य सामग्री पर अदा किए गए शुल्कों की औसत राशि;

(च) कोई भी अन्य जानकारी जो केंद्र सरकार इस उद्देश्य हेतु प्रासंगिक या उपयोगी मानती है।

**4. दरों का संशोधन -** केंद्र सरकार नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित राशि या दरों में संशोधन कर सकती है।

**5. तारीख का निर्धारण जिससे प्रतिअदायगी की राशि या दर लागू होती है और प्रतिअदायगी की राशि या दर के लगाने हेतु प्रभावी तिथि -**

(1) केन्द्र सरकार उस अवधि को निर्दिष्ट कर सकती है, जिस तक नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित या नियम 4 के अंतर्गत संशोधित, जैसा भी मामला हो, प्रतिअदायगी की कोई राशि या दर लागू होगी।

(2) जहां पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रतिअदायगी की राशि या दर की अनुमति दी गयी है, ऐसी राशि या दर को ऐसी तिथि से अनुमत किया जाएगा, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जो कि निर्यात वस्तुओं में प्रयोग किए गए इनपुट पर शुल्क की दरों में परिवर्तन की तारीख से पहले नहीं होगी।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 16, या धारा 83 की उप-धारा (2) के प्रावधान, इन नियमों के अंतर्गत निर्यात किए गए किसी माल पर लागू प्रतिअदायगी की राशि या दर निर्धारित करेंगे।

**6. मामले जहां प्रतिअदायगी की राशि या दर को निर्धारित नहीं किया गया है -**

(1) (क) जहाँ किसी भी वस्तु के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर निर्धारित नहीं की गई है, तो ऐसी वस्तुओं का निर्यातक, नियम 5 के उप-नियम (3) के अनुसार प्रतिअदायगी की राशि या दर के प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक तिथि के तीन महीनों के भीतर, सीमा शुल्क के प्रमुख आयुक्त या आयुक्त के पास, जिनके पास निर्यात के स्थान पर अधिकार क्षेत्र है, प्रतिअदायगी की राशि या दर के निर्धारण के लिए, उसके सभी प्रासंगिक तथ्यों के साथ और जिस अनुपात में सामग्रियों या घटकों का उपयोग माल के उत्पादन या निर्माण में किया गया हो और ऐसे सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किये गये शुल्क को बताते हुए आवेदन कर सकता है:

बशर्ते कि

(i) यदि निर्यातक निर्यात के एक से अधिक स्थानों से उपरोक्त सामान का निर्यात कर रहा है, तो वह सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जो निर्यात के किसी एक उपरोक्त स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखता है, के पास आवेदन करेगा।

(ii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, तीन महीने की अवधि तक, उपरोक्त तीन महीने की पूर्व अवधि का विस्तार कर सकता है और सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, यह अवधि और छह महीनों तक बढ़ा सकता है;

(iii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सीमा शुल्क का प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर और ऐसे जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझता है, विस्तार दे सकता है या इनकार के कारणों को लिखित में रिकॉर्डिंग के पश्चात् विस्तार देने से इंकार कर सकता;

(iv) निर्यात शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा विस्तार के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए देय होगा, और एफओबी मूल्य के 2% या दो हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तार के अनुदान हेतु आवेदन किए जाने के लिए देय होगा;

(ख) खंड (क) के तहत आवेदन की प्राप्ति पर, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसी जांच करने के बाद या ऐसी जांच करवाने के बाद जैसा उचित समझा जाए, ऐसी वस्तुओं के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण करेगा।

(2) (क) जहां एक निर्यातक चाहता है कि उसे अनंतिम रूप से प्रतिअदायगी दिया जाए, वह उप-नियम (1) की धारा (क) के तहत आवेदन करते समय सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के पास आवेदन कर सकता है कि उसको ऐसे सामानों के निर्यात पर प्रतिअदायगी की अनंतिम राशि दी जाए जब तक उस उप-नियम के खंड (ख) के तहत प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण नहीं हो जाता।

(ख) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर विचार करने के बाद, अनंतिम रूप से राशि का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है जो की निर्यातक द्वारा ऐसे निर्यात के संबंध में दावा की गई राशि से अधिक नहीं हो सकती:

बशर्ते कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, इस तरह के निर्यात के संबंध में प्रतिअदायगी के अनंतिम भुगतान की अनुमति देने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष कर सकता है कि निर्यातक को ऐसी रकम के लिए एक सामान्य बांड में प्रवेश करना होगा, और ऐसी परिस्थितियों के अधीन ही मिलेगा; या ऐसी रकम के लिए एक बांड में प्रवेश करना होगा जो की किसी विशेष खेप के संबंध में निर्यातक द्वारा दावा की गई प्रतिअदायगी की पूरी राशि से अधिक नहीं होगा और अपने आपको बाध्य करना होगा—

(i) अनंतिम रूप से स्वीकृत राशि वापस करने के लिए, यदि किसी भी कारण से यह पाया जाता है कि प्रतिअदायगी स्वीकार्य नहीं थी; या

(ii) अधिक राशि वापसी करने के लिए, यदि कोई हो, यदि यह पाया जाता है कि प्रति अदायगी की देय राशि ऐसे निर्यातक को अनंतिम रूप से भुगतान की जा चुकी राशि से कम थी:

बशर्ते कि जब ऐसे सामानों पर प्रति अदायगी की देय राशि या दर का अंत में निर्धारित किया जाता है, तो इस तरह के निर्यातक को अनंतिम रूप से भुगतान की गयी राशि को अंततः प्रतिअदायगी की देय राशि के खिलाफ समायोजित किया जाएगा और यदि समायोजित राशि अंततः प्रतिअदायगी की देय राशि से अधिक है या कम है, तो ऐसे निर्यातक को, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को अतिरिक्त राशि चुकानी होगी या वो कमी का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो।

(ग) खंड (ख) में निर्दिष्ट बांड, ऐसी जमानत या सुरक्षा के साथ हो सकता है जैसा कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, प्रत्यक्ष कर सकता है।

(3) जहां केंद्र सरकार इसे करने की आवश्यक समझती है, वो —

(क) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा उप-नियम (1) के खंड (ख) के तहत निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को रद्द कर सकती है; या

(ख) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को वापस लेने के लिए निर्देश दे सकती है।

**स्पष्टीकरण-** इस नियम के उद्देश्य हेतु, “निर्यात के स्थान” का मतलब है सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के तहत निर्यात माल की लोडिंग के लिए नियुक्त कोई अन्य जगह जहां से निर्यातक ने वो माल जिन के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण मांगा गया है निर्यात किया है या करने का इरादा रखता है।

## 7. मामले जिनमें निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर कम है -

(1) जहां किसी भी वस्तु के संबंध में, निर्यातक को पता चलता है कि नियम 3 के तहत निर्धारित और नियम 4 के तहत संशोधित, जैसा भी मामला हो, वस्तु की श्रेणी के लिए प्रतिअदायगी की राशि या दर, वस्तुओं के निर्माण या उत्पाद में इस्तेमाल किए गए सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किये गये शुल्क के अस्सी प्रतिशत से कम है, तो वो नियम 5 के उप-नियम (3) के अनुसार प्रतिअदायगी की राशि या दर के प्रयोज्यता के लिए प्रासंगिक तिथि के तीन महीनों के भीतर, जहां नियम 3 या नियम 4 के तहत प्रतिअदायगी का दावा न किया गया हो, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पास, जिनके पास निर्यात के स्थान पर अधिकार क्षेत्र है, प्रतिअदायगी की राशि या दर के निर्धारण के लिए, उसके सभी प्रासंगिक तथ्यों के साथ और जिस अनुपात में सामग्रियों या घटकों का उपयोग माल के उत्पादन या निर्माण में किया गया हो और ऐसे सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किया गया शुल्क को बताते हुए आवेदन कर सकता है:

बशर्ते कि -

(i) यदि निर्यातक निर्यात के एक से अधिक स्थानों से उपरोक्त सामान का निर्यात कर रहा है, तो वह सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जो निर्यात के किसी एक उपरोक्त स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखता है, के पास आवेदन करेगा।

(ii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, तीन महीने की अवधि तक, उपरोक्त तीन महीने की पूर्व अवधि का विस्तार कर सकता है और सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, यह अवधि और छह महीनों तक बढ़ा सकता है;

(iii) सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सीमा शुल्क का प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर और ऐसे जांच करने के बाद, जैसा वह उचित समझता है, विस्तार दे सकता है या इनकार के कारणों को लिखित में रिकॉर्डिंग के पश्चात् विस्तार देने से इंकार कर सकता;

(iv) निर्यात शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा कि मामला हो, द्वारा विस्तार के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए देय होगा, और एफओबी मूल्य के 2% या दो हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तार के अनुदान हेतु आवेदन किए जाने के लिए देय होगा;

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, ऐसी जांच करने के बाद या ऐसी जांच करवाने के बाद जैसा उचित समझा जाए, निर्यातक को ऐसी निर्धारित राशि या दर जैसा कि उचित हो पर प्रतिअदायगी का भुगतान करने की अनुमति दे सकता है, यदि नियम 3 के तहत निर्धारित और नियम 4 के तहत संशोधित प्रतिअदायगी की राशि या दर, जैसा भी मामला हो, वास्तव में इस उप-नियम के तहत निर्धारित राशि या दर के अस्सी प्रतिशत से कम है।

(3) सीमा शुल्क के उचित अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनंतिम प्रतिअदायगी राशि का भुगतान किया जायेगा, और जहां निर्यातक इच्छा रखता है कि उन्हें आगे और प्रतिअदायगी अनंतिम रूप से दी जाये, वह नियम 6 के उप-नियम (2) के खंड (क) में दिए गए आवेदन की विधि के अनुसार पहले से ही भुगतान किए गए अनंतिम प्रतिअदायगी के विवरण के साथ, उप-नियम (1) के तहत आवेदन करने के समय, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को आवेदन कर सकता है, और आगे और अनंतिम प्रतिअदायगी की अनुमति को इस तरीके से और उप-नियम (2) के खंड (ख) और (ग) और नियम 6 के उप-नियम (3) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन माना जाएगा, बशर्ते कि दावेदार द्वारा निष्पादित आवश्यक बांड केवल नियम 3 के तहत निर्धारित या नियम 4 के तहत केंद्र सरकार द्वारा संशोधित प्रतिअदायगी की राशि या दर, जैसा भी मामला हो, और सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा इस नियम के अंतर्गत अधिकृत अनंतिम प्रतिअदायगी, के अंतर के लिये ही निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) जहां केंद्र सरकार इसे करने की आवश्यक समझती है, वो -

(क) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा उप-नियम (2) के तहत निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को रद्द कर सकती है; या

(ख) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर को वापस लेने के लिए निर्देश दे सकती है।

**स्पष्टीकरण-** इस नियम के उद्देश्य हेतु, “निर्यात के स्थान” का मतलब है सीमा शुल्क स्टेशन या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के तहत निर्यात माल की लोडिंग के लिए नियुक्त कोई अन्य जगह जहाँ से निर्यातक ने वो माल जिन के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर का निर्धारण मांगा गया है निर्यात किया है या करने का इरादा रखता है।

**8. मामले जिनमें प्रतिअदायगी की कोई राशि या दर निर्धारित नहीं करनी है -** नियम 6 या नियम 7 के अंतर्गत, जैसा कि मामला हो, किसी भी माल या माल की श्रेणी के संबंध में प्रतिअदायगी की कोई राशि या दर को निर्धारित नहीं किया जाएगा यदि निर्यात के बिल या पोतपरिवहन बिल में ऐसे प्रत्येक माल या माल की श्रेणी का मूल्य ऐसे माल या माल के वर्ग के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली आयातित सामग्रियों के मूल्य से कम है, या सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी माल या माल की श्रेणी के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले आयातित सामग्रियों के मूल्य की निर्दिष्ट ऐसी प्रतिशतता से अधिक नहीं है।

**9. प्रतिअदायगी राशि या दर की ऊपरी सीमा -** नियम 3 के अंतर्गत निर्धारित प्रतिअदायगी राशि या दर निर्यात उत्पाद के बाजार मूल्य के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

**10. सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की शक्ति -**

(क) माल के उत्पादन या निर्माण में उपयोग किए जाने वाली सामग्रियों या घटकों की श्रेणी या विवरण का निर्धारण करने या ऐसी सामग्रियों या घटकों पर भुगतान किए गए शुल्क की राशि का निर्धारण करने; या

(ख) प्रतिअदायगी की राशि या दर के निर्धारण के संबंध में किसी निर्माता या निर्यातक या अन्य व्यक्तियों द्वारा दी किसी भी जानकारी की शुचिता अथवा अन्यथा की पुष्टि करने; या

(ग) प्रतिअदायगी हेतु किसी दावे की शुचिता अथवा अन्यथा का सत्यापन करने; या

(घ) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क के आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा आवश्यक अथवा उपयोगी समझे जाने वाली कोई अन्य सूचना को प्राप्त करने के,

प्रयोजन हेतु सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा इस पक्ष में प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी किसी निर्माता या माल के निर्यातक या किसी अन्य व्यक्ति जिसके पास ऐसी सूचना होने की सम्भावना हो को ऐसी सूचना देने अथवा लेखा-पुस्तिका और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बोल सकता है जैसा कि वो अधिकारी आवश्यक समझता है।

**11. कारखाना तक पहुंच -** केंद्र सरकार के किसी अधिकारी, जिसको विशेष रूप से इस संबंध में सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या सीमा शुल्क के उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, के द्वारा अधिकृत किया जाता है के आवश्यक समझने पर, निर्माता सभी उचित समय पर, उस परिसर के हर हिस्से तक जहां माल का निर्माण किया जाता है, उस अधिकृत अधिकारी को पहुंच प्रदान करेगा, ताकि वो अधिकारी निर्माण की प्रक्रिया को, और ऐसे माल के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री या घटकों को, या प्रतिअदायगी के लिए ऐसे माल की या प्रतिअदायगी की किसी विशेष राशि या दर के लिए इन नियमों के अधीन पात्रता को, निरीक्षण द्वारा सत्यापित करने हेतु सक्षम हो सके।

**12. डाक द्वारा निर्यात किए गए माल पर प्रतिअदायगी का दावा करने की प्रक्रिया -**

(1) जहां इन नियमों के अंतर्गत प्रतिअदायगी के दावे के अंतर्गत डाक द्वारा माल निर्यात किया जाना हो,-

(क) परेषिती के पते वाली बाहरी पैकिंग पर बड़े अक्षरों में "प्रतिअदायगी निर्यात" भी लिखा होना चाहिए;

(ख) निर्यातक, सक्षम डाक प्राधिकारी को, पार्सल या पैकेज सहित अनुबंध-1 में विधिवरूप से भरे प्रपत्र में दावे की चार प्रतियां सुपुर्द करेगा।

(2) डाक प्राधिकारियों से सीमा शुल्क के उचित अधिकारी द्वारा उपरोक्त दावा प्रपत्र की प्राप्ति की तिथि, धारा 75क के प्रयोजन हेतु निर्यातक द्वारा प्रतिअदायगी का दावा फाइल किए जाने की तिथि समझा जाएगा और इसके बारे में निर्यातक को सीमा शुल्क के उचित अधिकारी द्वारा एक सूचना, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, के द्वारा निर्धारित किए गये स्वरूप में, देनी होगी।

(3) यदि उपरोक्त दावा प्रपत्र सभी पहलुओं से पूर्ण नहीं है, तो निर्यातक को सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित स्वरूप में एक कमी ज्ञापन द्वारा डाक प्राधिकारियों से इसकी प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर इसकी कमियों को सूचित किया जाएगा, और इस तरह के दावे को उप-नियम (2) के प्रयोजन हेतु प्राप्त हुआ नहीं माना जाएगा।

(4) जब निर्यातक वापसी के तीस दिनों के भीतर कमी ज्ञापन में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो उसे सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित स्वरूप में उचित अधिकारी द्वारा अभिस्वीकृति जारी की जाएगी और ऐसी अभिस्वीकृति की तिथि, धारा 75क के प्रयोजन के लिए दावा दायर किए जाने की तिथि मानी जाएगी।

### 13. डाक के अलावा निर्यातों पर किया गया वक्तव्य/घोषणा -

(1) डाक के अलावा निर्यात के मामले में निर्यातक माल के निर्यात के समय -

(क) पोतपरिवहन बिल या निर्यात के बिल पर, विवरण, मात्रा और ऐसे अन्य व्यौरे का उल्लेख करेगा जैसे कि यह निर्धारित करने के लिए जरूरी है कि माल प्रतिअदायगी के लिए हकदार हैं, और यदि ऐसा है, तो किस दर या दरों पर और संबंधित पोतपरिवहन बिल या निर्यात बिल पर घोषणा करेगा कि-

(i) इन नियमों के अंतर्गत प्रतिअदायगी का दावा किया जा रहा है;

(ii) कंटेनरों, सामग्री की पैकिंग और निर्यात सामानों जिस पर प्रतिअदायगी का दावा किया गया है के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सामान पर भुगतान किए गए सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट के लिए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 या किसी अन्य कानून के अंतर्गत कोई अलग दावा नहीं किया गया है अथवा नहीं किया जाएगा;

वर्तते कि यदि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट हैं कि निर्यातक या उनके अधिकृत एजेंट, उसके नियंत्रण से परे के कारणों से, इस खंड के प्रावधानों का अनुपालन करने में असफल रहे हैं, तो वह, ऐसे निर्यातक या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार किए जाने के पश्चात् और कारणों को रिकार्ड करने पर, इस खंड के प्रावधानों से ऐसे निर्यातक या उसके अधिकृत एजेंट को छूट प्रदान कर सकता है;

(ख) सीमा शुल्क के उचित अधिकारी को, शिपमेंट विजक की एक प्रति या निर्यात किए जाने वाले सामानों के विवरण, मात्रा और मूल्य के व्यौरे देने वाला कोई अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।

(2) जहां नियम 6 या नियम 7 के अंतर्गत प्रतिअदायगी की राशि या दर निर्धारित की गई है, निर्यातक संगत शिपिंग बिल या निर्यात के बिल पर अतिरिक्त घोषणा करेगा कि -

(क) निर्माण सूत्रों और निर्यात माल के निर्माण में प्रयुक्त आयातित सामग्री या घटक की प्रति इकाई मात्रा में, यदि कोई हो, कोई बदलाव नहीं है; तथा

(ख) सामग्री या घटक, जिसका नियम 6 या नियम 7 के अंतर्गत आवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि इनका आयात किया गया है, आयात किया जाना जारी है और स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

### 14. डाक के अलावा निर्यातित माल पर प्रतिअदायगी दावा किए जाने हेतु तरीका और समय-

(1) प्रतिअदायगी के दावे के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) में इलेक्ट्रॉनिक शिपिंग बिल या प्रतिअदायगी के दावे के अंतर्गत माल के निर्यात हेतु पोतपरिवहन बिल की तीसरी प्रति को, धारा 51 के अंतर्गत निर्यात किए जाने हेतु माल की निकासी और लदान से जुड़े आदेश को उचित सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा किए जाने की तिथि पर प्रतिअदायगी का दावा माना जाएगा और प्रतिअदायगी के उक्त दावे को ऐसा आदेश जारी करने वाले उचित अधिकारी द्वारा रखा जाएगा।

(2) प्रतिअदायगी हेतु उक्त दावा निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होना चाहिए, अर्थात्: -

(i) निर्यात अनुबंध या साख-पत्र, जैसा भी मामला हो, की प्रति;

(ii) एआरई -1, जहां भी लागू हो, की प्रतिलिपि;

(iii) व्रीमा प्रमाणपत्र, जहां भी आवश्यक हो; और

(iv) प्रतिअदायगी की दर के संबंध में संचार की प्रतिलिपि, जहां प्रतिअदायगी का दावा इन नियमों के नियम 6 या नियम 7 के तहत सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित किसी दर हेतु है।

(3)(क) यदि प्रतिअदायगी का उक्त दावा किसी भी मसौदा विवरणों में अधूरा है या उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के बिना है, तो 10 दिनों के भीतर सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित स्वरूप में एक कमी जापन के साथ दावाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और धारा 75क के प्रयोजन हेतु दायर नहीं किया गया माना जाएगा।

(ख) जहां निर्यातक ने कमी के जापन में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के पालन के बाद प्रतिअदायगी के दावे को फिर से प्रस्तुत किया है, उसको अनुभाग 75क के प्रयोजन हेतु, उप-नियम (1) के अंतर्गत दायर दावे के रूप में माना जाएगा।

(4) दावाकर्ता को प्रतिअदायगी के भुगतान हेतु धारा 75क के अंतर्गत निर्धारित एक महीने की अवधि की गणना के लिए, निर्यात वस्तुओं के परीक्षण में लिया गया समय, एक माह से अधिक नहीं, को हटाया जाएगा।

### 15. प्रतिअदायगी और ब्याज का भुगतान -

(1) इन नियमों के तहत प्रतिअदायगी और ब्याज, यदि कोई हो, उचित सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा निर्यातक को या विशेष रूप से प्रतिअदायगी और ब्याज की उक्त राशि को प्राप्त किए जाने हेतु निर्यातक द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को अदा की जाएगी।

(2) सीमा शुल्क का अधिकारी प्रतिअदायगी और ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान के साथ-साथ पहले से अदा की गई प्रतिअदायगी की किसी राशि और ब्याज के समायोजन के लिए, एक या एक से अधिक दावों को जोड़ सकता है और भुगतान के लिए एक समेकित आदेश जारी कर सकता है।

(3) प्रतिअदायगी और ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान की तिथि को, -

(क) चेक द्वारा भुगतान के मामले में, ऐसे चेक जारी करने की तिथि; या

(ख) सीमा शुल्क सदन के साथ बनाए गए निर्यातक के खाते में क्रेडिट द्वारा भुगतान के मामले में, इस तरह के क्रेडिट की तिथि, माना जायेगा।

### 16. पूरक दावे -

(1) जहां किसी भी निर्यातक को पता चलता है कि उसे भुगतान की गई प्रतिअदायगी की राशि केंद्रीय सरकार या सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित प्रतिअदायगी की राशि या दर के आधार पर हकदार होने की तुलना में कम है तो वह अनुबंध-II के प्रपत्र में एक पूरक दावे को तरजीह दे सकता है:

बशर्ते कि निर्यातक ऐसे पूरक दावे को -

(i) जहां नियम 3 या नियम 4 के तहत प्रतिअदायगी की दर निर्धारित या संशोधित की गयी हो, शासकीय राजपत्र में ऐसी दर के प्रकाशन की तारीख से; या

(ii) जहां प्रतिअदायगी की दर को नियम 6 या नियम 7 के तहत निर्धारित या ऊपर की ओर संशोधित की गयी हो, संबंधित व्यक्ति को उक्त दर को संप्रेषित करने की तारीख से; या

(iii) अन्य सभी मामलों में, उचित अधिकारी द्वारा मूल प्रतिअदायगी के दावों के भुगतान या निपटान की तारीख से,

तीन महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करता है:



वशर्ते और आगे कि -

(i) सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, उपरोक्त तीन महीने की अवधि को नौ महीने की अवधि तक विस्तार कर सकता है और यह कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, अवधि को छह महीनों तक और बढ़ा सकता है;

(ii) सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त या सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, आवेदन पर और ऐसी जांच करने के बाद जैसा वह उचित समझता है, विस्तार दे सकता है या इनकार के कारणों को लिखित में रिकॉर्डिंग के पश्चात् विस्तार देने से इंकार कर सकता है;

(iii) निर्यात शुल्क के एफओबी मूल्य के 1% या एक हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा कि मामला हो, द्वारा विस्तार के अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए देय होगा, और एफओबी मूल्य के 2% या दो हजार रुपये जो भी कम है के बराबर आवेदन शुल्क सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा विस्तार के अनुदान हेतु आवेदन किए जाने के लिए देय होगा।

(2) इस नियम में अन्यथा उपलब्ध कराए जाने के रूप में सहेजे, प्रतिअदायगी हेतु किसी पूरक दावे को नहीं माना जाएगा।

(3) धारा 75 के प्रयोजन हेतु पूरक दावे को फाइल करने की तिथि, जो कि सभी मामलों में पूर्ण हो, ऐसे दावों पर दिनांकित रसीद स्टाम्प को लागू करने की तिथि होगी और जिसके लिए सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त, या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित स्वरूप में एक अभिस्वीकृति जारी की जाएगी।

(4)(क) ऐसे दावे जो सभी मामलों में पूर्ण नहीं हैं या आवश्यक दस्तावेजों के साथ नहीं हैं, उन्हें दावेदार को सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त, या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा निर्धारित स्वरूप में एक कमी ज्ञापन के साथ प्रस्तुत किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर वापस किया जाएगा और इसे दायर नहीं किया जाना माना जाएगा।

(ख) जहां निर्यातक कमी ज्ञापन में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुपालन के बाद पूरक दावे को फिर से जमा करता है, वही अनुभाग 75 के प्रयोजन हेतु, उप-नियम (1) के तहत दायर दावे के रूप में माना जाएगा।

**17. प्रतिअदायगी और ब्याज के गलत या अधिक भुगतान का पुनर्भुगतान -** जहां प्रतिअदायगी की राशि और ब्याज, यदि कोई हो, का भुगतान गलती से किया गया हो या ऐसे भुगतान की गई राशि दावेदार की हकदारी से अधिक है, तो दावेदार, उचित सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा मांग पर ऐसे गलती से भुगतान की गई या अधिक भुगतान की गई राशि, जैसा भी मामला हो, को चुकाएगा और जहां दावेदार राशि चुकाने में विफल रहता है, तो इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 142 की उप-धारा (1) में निर्धारित ढंग में वसूल किया जाएगा।

**18. प्रतिअदायगी की राशि की वसूली जहां निर्यात आय की प्राप्ति न हुई हो -**

(1) जहां किसी निर्यातक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति (एतश्मिनपश्चात् दावेदार के रूप में संदर्भित) को प्रतिअदायगी की राशि का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन ऐसी निर्यात वस्तुओं के संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अंतर्गत अनुमत अवधि के भीतर, ऐसी अवधि के किसी विस्तार सहित, भारत में निर्यातक द्वारा या उसकी ओर से निर्यात आय की उगाही नहीं की गई है, तो ऐसी प्रतिअदायगी, उप-नियम (5) में निर्दिष्ट परिस्थितियों या शर्तों को छोड़कर, नीचे निर्दिष्ट तरीके से वसूल किया जाएगा :

वशर्ते कि इस उप-नियम में संदर्भित समय-सीमा घरेलू टेरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्यातित माल पर लागू नहीं होगी।

(2) यदि निर्यातक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत अनुमत अवधि या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उक्त अवधि का कोई विस्तार, के भीतर निर्यात की उगाही के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, निर्यातक को नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्यात की उगाही के संबंध में प्रमाण प्रस्तुति हेतु नोटिस जारी करेगा और जहां निर्यातक तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता है तो सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, दावेदार को अदा की गई प्रतिअदायगी की राशि वसूली हेतु एक आदेश पास करेगा और निर्यातक उक्त आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी मांग की गई राशि को चुकाएगा :

बशर्ते कि जहां बिक्री प्राप्ति के एक हिस्से की उगाही हो गई है, वसूली किए जाने हेतु प्रतिअदायगी की राशि उस हिस्से के बराबर की राशि होगी जिसका भुगतान की गई राशि के साथ वही अनुपात है, जो अनुपात उगाही नहीं की गई राशि का बिक्री प्राप्ति की कुल राशि से है।

(3) जहां निर्यातक उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि के भीतर उप-नियम (2) के तहत राशि चुकाने में विफल रहता है, तो इसे नियम 17 में निर्धारित तरीके से वसूल किया जाएगा।

(4) जहां निर्यातक उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के तहत उससे प्रतिअदायगी की राशि को वसूलने के बाद, बिक्री प्राप्ति की उगाही कर लेता है और निर्यातक तीन महीनों की अवधि के भीतर इस तरह की प्राप्ति के बारे में प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो ऐसे वसूल की गई प्रतिअदायगी की राशि को सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा दावाकर्ता को चुकाया जाएगा बशर्ते बिक्री प्राप्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमत अवधि के भीतर वसूली गई हों :

बशर्ते कि-

(i) सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, उपर्युक्त तीन महीने की अवधि को नौ महीने की अवधि तक बढ़ा सकते हैं, बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अवधि के भीतर बिक्री प्राप्तियों की उगाही की गई हो;

(ii) निर्यात शुल्क के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत या एक हजार रुपये, जो भी कम हो, के समतुल्य आवेदन शुल्क, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा विस्तार की मंजूरी हेतु आवेदन किए जाने के लिए देय होगा।

(5) जहां विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत अनुमत अवधि के भीतर किसी निर्यातक द्वारा बिक्री प्राप्ति की उगाही नहीं हुई है, लेकिन बिक्री प्राप्ति का ऐसा गैर-उद्ग्रहण का मुआवजा बीमा कवर के अंतर्गत भारतीय निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा दिया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक बिक्री प्राप्ति के उद्ग्रहण की अपेक्षा को बढ़े खाते में डालता है और निर्यातक क्रेता से बिक्री प्राप्ति की गैर-वसूली के तथ्य के बारे में संबंधित विदेशी भारतीय मीशन से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है, तो निर्यातक अथवा प्रतिनिधि को अदा किए गए प्रतिअदायगी की राशि को वसूला नहीं जाएगा।

**19. छूट की शक्ति** - यदि केंद्र सरकार संतुष्ट है कि किसी भी सामान के निर्यात के संबंध में, निर्यातक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, उसके नियंत्रण से परे कारणों से, इन नियमों के किसी भी प्रावधान का पालन नहीं कर पा रहे हैं और इस प्रकार वह प्रतिअदायगी के हकदार हैं, तो ऐसे निर्यातक या प्रतिनिधि द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसे नियम के प्रावधानों से ऐसे निर्यातक या प्रतिनिधि को छूट प्रदान कर सकते हैं और ऐसे माल के संबंध में प्रतिअदायगी की अनुमति दे सकते हैं।

## 20. निरसन और बचत -

(1) इन नियमों की शुरुआत से, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 को संचालित करना बंद कर दिया जाएगा।

(2) ऐसे संचालन की निवृत्ति के बावजूद -

(क) इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले निर्यात किए गए माल के संबंध में प्रतिअदायगी की राशि या दर के निर्धारण या संशोधन के लिए किसी निर्माता या निर्यातक द्वारा किए गए प्रत्येक आवेदन, किंतु जिनका ऐसी शुरुआत होने से पूर्व निपटान नहीं किया गया, उनका सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुसरण में निपटान किया जाएगा, जैसे कि ये नियम बनाए नहीं गए थे;

(ख) इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व निर्यात किए गए माल के संबंध में किसी निर्यातक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिअदायगी की अदायगी हेतु दावा किया गया हो किंतु ऐसी शुरुआत होने से पूर्व निपटान नहीं किया गया, उनका सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुसरण में निपटान किया जाएगा, जैसे कि ये नियम बनाए नहीं गए थे;

(ग) सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के अंतर्गत निर्धारित और इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले प्रभावी प्रतिअदायगी की प्रत्येक राशि या दर, इन नियमों के प्रारंभ या उसके बाद निर्यात किए गए माल के संबंध में काम करना बंद कर देंगे।

[फा. सं. 609/75/2017-डीबीके]

आनंद कुमार झा, अवर सचिव

**अनुबंध-I**

नियम 12 के अंतर्गत प्रतिअदायगी के दावे हेतु प्रपत्र

मूल  
प्रतिलिपि  
तीसरी प्रति  
चौथी प्रति**भाग-I**

डीबीके. संदर्भ

चालान सं.

दिनांक:

प्रतिअदायगी हेतु दावे के अंतर्गत पार्सल डाक द्वारा निर्यात किए जाने हेतु माल का ब्यौरा

प्रपत्र सं.

सेवा में

सहायक/उपायुक्त, सीमा शुल्क (प्रतिअदायगी)

विदेशी डाकघर

हम, \_\_\_\_\_ अधोलिखित समनुदेशन के निर्यात किए जाने का प्रस्ताव करते हैं।

समनुदेशी का नाम और पता \_\_\_\_\_ |

क्र. सं.	पार्सलो की तिथि	सकल भार	मदो पर अंक/संख्या	मात्रा	एफओबी मूल्य	डीबीके की दर	भार	राशि रु. पै.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1. सत्यापित किया जाता है कि निर्माण के पश्चात माल का प्रयोग नहीं किया गया था।
2. प्रमाणित किया जाता है कि शुल्क की छूट हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 18 या नियम 19 के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के पास अलग से दावा नहीं किया गया है और नहीं किया जायेगा और यह कि माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया है। हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि यहां की गई घोषणा सच्ची और सही है।

जो कुछ भी लागू नहीं है, उसे हटा दें।

निर्यातक की कार्यालय मोहर

हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

**भाग-II**

मैंने उपरोक्त पार्सल की जांच की है जिसमें उपरोक्त ब्यौरा \_\_\_\_\_ समाविष्ट है। पार्सलों को मेरी उपस्थिति में पैक किया गया है और लेड/मोम मोहर सं. \_\_\_\_\_ के साथ मेरे द्वारा मुहरबंद किया गया है जिसका निम्नलिखित विवरण \_\_\_\_\_ है।

दिनांक:

समनुदेशन की जांच और मोहरबंद करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान:

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त नोट किए गए पार्सलों को मेरे अधीक्षण के अंतर्गत जांच कर, पैक और मोहरबंद किया गया था ।

तिथि: अधीक्षक, सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के हस्ताक्षर

स्थान:

### भाग-III

अधीक्षक, विदेशी डाकघर, नई दिल्ली को \_\_\_\_\_ पार्सल सहित अग्रेषित । डाक रसीद सं. \_\_\_\_\_

डाक पाल

डाक घर

डाकघर की मोहर और तिथि

### भाग-IV

\_\_\_\_\_ पार्सलों का निरीक्षण किया गया और मोहर को यथावत् पाया गया । \_\_\_\_\_  
पार्सलों की जांच-पड़ताल की गई जहां मोहरों को अछूता नहीं पाया गया \_\_\_\_\_

निर्यात के लिए पास करें ।

कृपया आगे की कार्रवाई के लिए रोके ।

परीक्षक/जांचकर्ता के हस्ताक्षर  
डाक मूल्यांकन विभाग

दिनांक:

स्थान:

कार्यालय की मोहर

\_\_\_\_\_  
(स्थान)

### भाग-V

सत्यापित किया गया है कि यहां वर्णित पार्सल को \_\_\_\_\_ द्वारा हवाई/समुद्री एक्स.एस.एस.  
\_\_\_\_\_ के द्वारा \_\_\_\_\_ को भारत से निर्यात किया गया है । आयुक्त/प्रधान  
आयुक्त, सीमा शुल्क \_\_\_\_\_ को अग्रेषित किया गया ।

स्थान:

दिनांक:

अधीक्षक के हस्ताक्षर

विदेशी डाकघर

**अनुबंध-II**

सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 2017 के नियम 16 के अंतर्गत प्रतिअदायगी के पूरक दावे हेतु आवेदन ।

(जहां सरकार द्वारा निर्धारित अंततः तय दर अपेक्षाकृत कम हो गई है, प्रतिअदायगी के अनुपूरक दावे के लिए आवेदन निम्न प्रपत्र में किया जाना चाहिए)

सेवा में

सहायक/उपायुक्त, प्रभारी-सीमा शुल्क  
प्रतिअदायगी विभाग

हम एतद्वारा सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिअदायगी हेतु एक अनुपूरक दावा करते हैं जो उसमें स्पष्ट किए अनुसार हमें कम भुगतान किया गया है ।

1. निर्यातक

- (क) नाम
- (ख) पता
- (ग) दूरभाष सं०.
- (घ) निकासी अभिकर्ता का नाम

2. निर्यातित माल

- (क) विवरण
- (ख) मात्रा
  - (i) सकल
  - (ii) निवल
- (ग) मार्किस और सं.
- (घ) गंतव्य
- (ङ.) पोतपरिवहन बिल सं. और तिथि

3. यान

- (क) नाम
- (ख) रोटेशन सं.

4. पहले ही भुगतान की गई प्रतिअदायगी

- (क) राशि
- (ख) सीमा शुल्क सदन संदर्भ सं.
- (ग) मात्रा/कीमत जिस पर अनुमत
- (घ) दर जिस पर अनुमत ।

5. दावा नहीं की गई प्रतिअदायगी

- (क) राशि
- (ख) मात्रा/कीमत जिस पर अनुमत
- (ग) दर जिस पर दावा किया गया

6. पूरक दावे हेतु कारण ।
7. संलग्न किए गए दस्तावेजों की सं.\*

### घोषणा

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि प्रतिअदायगी का पूरक दावा निर्यात किए गए माल के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर अदा किए गए सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर आधारित होता है और यह कि ऐसे भुगतान किए गए शुल्कों का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के अंतर्गत छूट के रूप में दावा नहीं किया गया है ।

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यहां की गई घोषणा सच्ची और सही है ।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

\* कृपया नियम 6 या 7 के तहत निर्धारित प्रतिअदायगी की दर, अनुपूरक दावे के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज, या प्रधान आयुक्त/आयुक्त, सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले कोई अन्य दस्तावेज के संबंध में संसूचना की प्रतिलिपि संलग्न करें ।

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2017

**No. 88/ 2017-CUSTOMS (N.T.)**

**G.S.R. 1177(E).**—In exercise of the powers conferred by section 75 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

#### 1. Short title, extent and commencement.-

- (1) These rules may be called the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017.
- (2) They extend to the whole of India.
- (3) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of October, 2017.

#### 2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) “drawback” in relation to any goods manufactured in India and exported, means the rebate of duty excluding integrated tax leviable under sub-section (7) and compensation cess leviable under sub-section (9) respectively of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) chargeable on any imported materials or excisable materials used in the manufacture of such goods;
- (b) “excisable material” means any material produced or manufactured in India subject to a duty of excise under the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
- (c) “export”, with its grammatical variations and cognate expressions, means taking out of India to a place outside India or taking out from a place in Domestic Tariff Area (DTA) to a special economic zone and includes loading of provisions or store or equipment for use on board a vessel or aircraft proceeding to a foreign port;
- (d) “imported material” means any material imported into India and on which duty is chargeable under the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (e) “manufacture” includes processing of or any other operation carried out on goods, and the term manufacturer shall be construed accordingly;

(f) “tax invoice” means the tax invoice referred to in section 31 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017).

**3. Drawback.**— (1) Subject to the provisions of –

- (a) the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the rules made thereunder;
- (b) the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder; and
- (c) these rules, a drawback may be allowed on the export of goods at such amount, or at such rates, as may be determined by the Central Government :

Provided that where any goods are produced or manufactured from imported materials or excisable materials, on some of which only the duty chargeable thereon has been paid and not on the rest, or only a part of the duty chargeable has been paid; or the duty paid has been rebated or refunded in whole or in part or given as credit, under any of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the rules made thereunder, or of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder, the drawback admissible on the said goods shall be reduced taking into account the lesser duty paid or the rebate, refund or credit obtained :

Provided further that no drawback shall be allowed –

- (i) if the said goods, except tea chests used as packing material for export of blended tea, have been taken into use after manufacture;
  - (ii) if the said goods are produced or manufactured, using imported materials or excisable materials in respect of which duties have not been paid;
  - (iii) on jute batching oil used in the manufacture of export goods, namely, jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre) yarn, twist, twine, thread, cords and ropes;
  - (iv) if the said goods, being packing materials have been used in or in relation to the export of -
    - (A) jute yarn (including Bimlipatam jute or mesta fibre), twist, twine, thread and ropes in which jute yarn predominates in weight;
    - (B) jute fabrics (including Bimlipatam jute or mesta fibre), in which jute predominates in weight;
    - (C) jute manufactures not elsewhere specified (including Bimlipatam jute or mesta fibre) in which jute predominates in weight.
- (2) In determining the amount or rate of drawback under this rule, the Central Government shall have regard to, -
- (a) the average quantity or value of each class or description of the materials from which a particular class of goods is ordinarily produced or manufactured in India;
  - (b) the average quantity or value of the imported materials or excisable materials used for production or manufacture in India of a particular class of goods;
  - (c) the average amount of duties paid on imported materials or excisable materials used in the manufacture of semis, components and intermediate products which are used in the manufacture of goods;
  - (d) the average amount of duties paid on materials wasted in the process of manufacture and catalytic agents:
 

Provided that if any such waste or catalytic agent is re-used in any process of manufacture or is sold, the average amount of duties on the waste or catalytic agent re-used or sold shall also be deducted;
  - (e) the average amount of duties paid on imported materials or excisable materials used for containing or, packing the export goods;
  - (f) any other information which the Central Government may consider relevant or useful for the purpose.

**4. Revision of rates.**— The Central Government may revise amount or rates determined under rule 3.

**5. Determination of date from which the amount or rate of drawback is to come into force and the effective date for application of amount or rate of drawback.**—

(1) The Central Government may specify the period upto which any amount or rate of drawback determined under rule 3 or revised under rule 4, as the case may be, shall be in force.

(2) Where the amount or rate of drawback is allowed with retrospective effect, such amount or rate shall be allowed from such date as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette which shall not be earlier than the date of changes in the rates of duty on inputs used in the export goods.

(3) The provisions of section 16, or sub-section (2) of section 83, of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) shall determine the amount or rate of drawback applicable to any goods exported under these rules.

**6. Cases where amount or rate of drawback has not been determined.-**

(1)(a) Where no amount or rate of drawback has been determined in respect of any goods, any exporter of such goods may, within three months from the date relevant for the applicability of the amount or rate of drawback in terms of sub-rule (3) of rule 5, apply to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the place of export, for determination of the amount or rate of drawback thereof stating all the relevant facts including the proportion in which the materials or components are used in the production or manufacture of goods and the duties paid on such materials or components:

Provided that-

(i) in case an exporter is exporting the aforesaid goods from more than one place of export, he shall apply to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, having jurisdiction over any one of the said places of export;

(ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of three months and the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;

(iii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;

(iv) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or one thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or two thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

(b) On receipt of an application under clause (a), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, shall, after making or causing to be made such inquiry as it deems fit, determine the amount or rate of drawback in respect of such goods.

(2)(a) Where an exporter desires that he may be granted drawback provisionally, he may, while making an application under clause (a) of sub-rule (1) apply to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, that a provisional amount be granted to him towards drawback on the export of such goods pending determination of the amount or rate of drawback under clause (b) of that sub-rule.

(b) The Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, after considering the application, allow provisionally payment of an amount not exceeding the amount claimed by the exporter in respect of such export:

Provided that the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, for the purpose of allowing provisional payment of drawback in respect of such export, require the exporter to enter into a general bond for such amount, and subject to such conditions, as he may direct; or to enter into a bond for an amount not exceeding the full amount claimed by such exporter as drawback in respect of a particular consignment and binding himself, -



- (i) to refund the amount so allowed provisionally, if for any reason, it is found that the duty drawback was not admissible; or
- (ii) to refund the excess, if any, paid to such exporter provisionally if it is found that a lower amount was payable as duty drawback:

Provided further that when the amount or rate of drawback payable on such goods is finally determined, the amount provisionally paid to such exporter shall be adjusted against the drawback finally payable and if the amount so adjusted is in excess or falls short of the drawback finally payable, such exporter shall repay to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, the excess or be entitled to the deficiency, as the case may be.

(c) The bond referred to in clause (b) may be with such surety or security as the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may direct.

(3) Where the Central Government considers it necessary so to do, it may,—

- (a) revoke the rate of drawback or amount of drawback, determined under clause (b) of sub-rule (1) by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be; or
- (b) direct the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, to withdraw the rate of drawback or amount of drawback determined.

*Explanation.*— For the purpose of this rule, “place of export” means customs station or any other place appointed for loading of export goods under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) from where the exporter has exported the goods or intends to export the goods in respect of which determination of amount or rate of drawback is sought.

#### **7. Cases where amount or rate of drawback determined is low.—**

(1) Where, in respect of any goods, the exporter finds that the amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be, revised under rule 4, for the class of goods is less than eighty per cent. of the duties paid on the materials or components used in the production or manufacture of the said goods, he may, except where a claim for drawback under rule 3 or rule 4 has been made, within three months from the date relevant for the applicability of the amount or rate of drawback in terms of sub-rule (3) of rule 5, make an application to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction over the place of export, for determination of the amount or rate of drawback thereof stating all relevant facts including the proportion in which the materials or components are used in the production or manufacture of goods and the duties paid on such materials or components:

Provided that -

- (i) in case an exporter is exporting the aforesaid goods from more than one place of export, he shall apply to the Principal Commissioner or Commissioner of Customs, having jurisdiction over any one of the said places of export;
- (ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of three months and that the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;
- (iii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, on an application and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;
- (iv) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or one thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or two thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

(2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1), the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, after making or causing to be made such inquiry as it deems fit, allow payment of drawback to such exporter at such amount or at such rate as may be determined to be appropriate, if the amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be, revised under rule 4, is in fact less than eighty per cent. of such amount or rate determined under this sub-rule.

(3) Provisional drawback amount, as may be specified by the Central Government, shall be paid by the proper officer of Customs and where the exporter desires that he may be granted further drawback provisionally, he may, while making an application under sub-rule (1), apply to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, in this behalf in the manner as has been provided in clause (a) of sub-rule (2) of rule 6 for the application made under that rule along with details of provisional drawback already paid and the grant of further provisional drawback shall be considered in the manner and subject to the conditions specified in clauses (b) and (c) of sub-rule (2), and sub-rule (3) of rule 6, subject to the condition that bond required to be executed by the claimant shall only be for the difference between amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be, revised under rule 4 by the Central Government and the provisional drawback authorised by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, under this rule.

(4) Where the Central Government considers it necessary so to do, it may,—

(a) revoke the rate of drawback or amount of drawback determined under sub-rule (2) by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be; or

(b) direct the Principal Commissioner of Customs or the Commissioner of Customs, as the case may be, to withdraw the rate of drawback or amount of drawback determined.

*Explanation.*— For the purpose of this rule, “place of export” means customs station or any other place appointed for loading of export goods under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) from where the exporter has exported the goods or intends to export the goods in respect of which determination of amount or rate of drawback is sought.

**8. Cases where no amount or rate of drawback is to be determined.**— No amount or rate of drawback shall be determined in respect of any goods or class of goods under rule 6 or rule 7, as the case may be, if the export value of each of such goods or class of goods in the bill of export or shipping bill is less than the value of the imported materials used in the manufacture of such goods or class of goods, or is not more than such percentage of the value of the imported materials used in the manufacture of such goods or class of goods as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf.

**9. Upper Limit of Drawback amount or rate.**— The drawback amount or rate determined under rule 3 shall not exceed one third of the market price of the export product.

**10. Power to require submission of information and documents.**— For the purpose of —

(a) determining the class or description of materials or components used in the production or manufacture of goods or for determining the amount of duty paid on such materials or components; or

(b) verifying the correctness or otherwise of any information furnished by any manufacturer or exporter or other persons in connection with the determination of the amount or rate of drawback; or

(c) verifying the correctness or otherwise of any claim for drawback; or

(d) obtaining any other information considered by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, to be relevant or useful, any officer of the Central Government specially authorised in this behalf by an Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may require any manufacturer or exporter of goods or any other person likely to be in possession of the same to furnish such information and to produce such books of account and other documents as are considered necessary by such officer.

**11. Access to manufactory.**— Whenever an officer of the Central Government specially authorised in this behalf by an Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, considers it necessary, the manufacturer shall give access at all reasonable times to the officer so authorised to every part of the premises in which the goods are manufactured, so as to enable the said officer to verify by inspection the process of, and the

materials or components used for the manufacture of such goods, or otherwise the entitlement of the goods for drawback or for a particular amount or rate of drawback under these rules.

### **12. Procedure for claiming drawback on goods exported by post.-**

(1) Where goods are to be exported by post under a claim for drawback under these rules,-

(a) the outer packing carrying the address of the consignee shall also carry in bold letters the words "DRAWBACK EXPORT";

(b) the exporter shall deliver to the competent Postal Authority, alongwith the parcel or package, a claim in the Form at Annexure I, in quadruplicate, duly filled in.

(2) The date of receipt of the aforesaid claim form by the proper officer of Customs from the postal authorities shall be deemed to be date of filing of drawback claim by the exporter for the purpose of section 75A and an intimation of the same shall be given by the proper officer of Customs to the exporter in such form as the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may prescribe.

(3) In case the aforesaid claim form is not complete in all respects, the exporter shall be informed of the deficiencies therein within fifteen days of its receipt from postal authorities by a deficiency memo in the form prescribed by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, and such claim shall be deemed not to have been received for the purpose of sub-rule (2).

(4) When the exporter complies with the requirements specified in the deficiency memo within thirty days of its return, he shall be issued an acknowledgement by the proper officer in the form prescribed by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, and the date of such acknowledgement shall be deemed to be date of filing the claim for the purpose of section 75A.

### **13. Statement/Declaration to be made on exports other than by Post.-**

(1) In the case of exports other than by post, the exporters shall at the time of export of the goods –

(a) state on the shipping bill or bill of export, the description, quantity and such other particulars as are necessary for deciding whether the goods are entitled to drawback, and if so, at what rate or rates and make a declaration on the relevant shipping bill or bill of export that-

(i) a claim for drawback under these rules is being made;

(ii) in respect of duties of Customs and Central Excise paid on containers, packing materials and materials used in the manufacture of the export goods on which drawback is claimed, no separate claim for rebate of duty under the Central Excise Rules, 2002 or any other law has been or will be made to the Central excise authorities:

Provided that if the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, is satisfied that the exporter or his authorised agent has, for reasons beyond his control, failed to comply with the provisions of this clause, he may, after considering the representation, if any, made by such exporter or his authorised agent, and for reasons to be recorded, exempt such exporter or his authorised agent from the provisions of this clause;

(b) furnish to the proper officer of Customs, a copy of shipment invoice or any other document giving particulars of the description, quantity and value of the goods to be exported.

(2) Where the amount or rate of drawback has been determined under rule 6 or rule 7, the exporter shall make an additional declaration on the relevant shipping bill or bill of export that –

(a) there is no change in the manufacturing formula and in the quantum per unit of the imported materials or components, if any, utilised in the manufacture of export goods; and

(b) the materials or components, which have been stated in the application under rule 6 or rule 7 to have been imported, continue to be so imported and are not being obtained from indigenous sources.

### **14. Manner and time for claiming drawback on goods exported other than by post.-**

(1) Electronic shipping bill in Electronic Data Interchange (EDI) under the claim of drawback or triplicate copy of the shipping bill for export of goods under a claim of drawback shall be deemed to be a claim for drawback filed on the date on which the proper officer of Customs makes an order permitting clearance and loading of

goods for exportation under section 51 and said claim for drawback shall be retained by the proper officer making such order.

(2) The said claim for drawback should be accompanied by the following documents, namely:-

(i) copy of export contract or letter of credit, as the case may be;

(ii) copy of ARE-1, wherever applicable;

(iii) insurance certificate, wherever necessary; and

(iv) copy of communication regarding rate of drawback where the drawback claim is for a rate determined by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, under rule 6 or rule 7 of these rules.

(3)(a) If the said claim for drawback is incomplete in any material particulars or is without the documents specified in sub-rule (2), shall be returned to the claimant with a deficiency memo in the form prescribed by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, within 10 days and shall be deemed not to have been filed for the purpose of section 75A.

(b) where the exporter resubmits the claim for drawback after complying with the requirements specified in the deficiency memo, the same will be treated as a claim filed under sub-rule (1) for the purpose of section 75A.

(4) For computing the period of one month prescribed under section 75A for payment of drawback to the claimant, the time taken in testing of the export goods, not more than one month, shall be excluded.

#### **15. Payment of drawback and interest.—**

(1) The drawback under these rules and interest, if any, shall be paid by the proper officer of Customs to the exporter or to the agent specially authorised by the exporter to receive the said amount of drawback and interest.

(2) The officer of Customs may combine one or more claims for the purpose of payment of drawback and interest, if any, as well as adjustment of any amount of drawback and interest already paid and may issue a consolidated order for payment.

(3) The date of payment of drawback and interest, if any, shall be deemed to be, in the case of payment –

(a) by cheque, the date of issue of such cheque; or

(b) by credit in the exporter's account maintained with the Custom House, the date of such credit.

#### **16. Supplementary claim. –**

(1) Where any exporter finds that the amount of drawback paid to him is less than what he is entitled to on the basis of the amount or rate of drawback determined by the Central Government or Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, he may prefer a supplementary claim in the form at Annexure II:

Provided that the exporter shall prefer such supplementary claim within a period of three months, -

(i) where the rate of drawback is determined or revised under rule 3 or rule 4, from the date of publication of such rate in the Official Gazette;

(ii) where the rate of drawback is determined or revised upward under rule 6 or rule 7, from the date of communicating the said rate to the person concerned;

(iii) in all other cases, from the date of payment or settlement of the original drawback claim by the proper officer:

Provided further that –

(i) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of nine months and that the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may further extend the period by a period of six months;

(ii) the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs or Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may, on an application

and after making such enquiry as he thinks fit, grant extension or refuse to grant extension after recording in writing the reasons for such refusal;

(iii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or one thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be and an application fee of 2% of the FOB value or two thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

(2) Save as otherwise provided in this rule, no supplementary claim for drawback shall be entertained.

(3) The date of filing of the supplementary claim for the purpose of section 75A shall be the date of affixing the Dated Receipt Stamp on such claims which are complete in all respects and for which an acknowledgement shall be issued in the form prescribed by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

(4)(a) Claims which are not complete in all respects or are not accompanied by the required documents shall be returned to the claimant with a deficiency memo in the form prescribed by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be within fifteen days of submission and shall be deemed not to have been filed.

(b) Where the exporter resubmits the supplementary claim after complying with the requirements specified in the deficiency memo, the same will be treated as a claim filed under sub-rule (1) for the purpose of section 75A.

**17. Repayment of erroneous or excess payment of drawback and interest.** - Where an amount of drawback and interest, if any, has been paid erroneously or the amount so paid is in excess of what the claimant is entitled to, the claimant shall, on demand by a proper officer of Customs repay the amount so paid erroneously or in excess, as the case may be, and where the claimant fails to repay the amount it shall be recovered in the manner laid down in sub-section (1) of section 142 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

**18. Recovery of amount of Drawback where export proceeds not realised. –**

(1) Where an amount of drawback has been paid to an exporter or a person authorised by him (hereinafter referred to as the claimant) but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realised by or on behalf of the exporter in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), including any extension of such period, such drawback shall, except under circumstances or conditions specified in sub-rule (5), be recovered in the manner specified below:

Provided that the time-limit referred to in this sub-rule shall not be applicable to the goods exported from the Domestic Tariff Area to a special economic zone.

(2) If the exporter fails to produce evidence in respect of realisation of export proceeds within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999, or any extension of the said period by the Reserve Bank of India, the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, shall cause notice to be issued to the exporter for production of evidence of realisation of export proceeds within a period of thirty days from the date of receipt of such notice and where the exporter does not produce such evidence within the said period of thirty days, the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, shall pass an order to recover the amount of drawback paid to the claimant and the exporter shall repay the amount so demanded within thirty days of the receipt of the said order:

Provided that where a part of the sale proceeds has been realised, the amount of drawback to be recovered shall be the amount equal to that portion of the amount of drawback paid which bears the same proportion as the portion of the sale proceeds not realised bears to the total amount of sale proceeds.

(3) Where the exporter fails to repay the amount under sub-rule (2) within said period of thirty days referred to in sub-rule (2), it shall be recovered in the manner laid down in rule 17.

(4) Where the sale proceeds are realised by the exporter after the amount of drawback has been recovered from him under sub-rule (2) or sub-rule (3) and the exporter produces evidence about such realisation within a period of three months from the date of realisation of sale proceeds, the amount of drawback so recovered shall be repaid by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, to the claimant provided the sale proceeds have been realised within the period permitted by the Reserve Bank of India:

Provided that-

(i) the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be, may extend the aforesaid period of three months by a period of nine months provided the sale proceeds have been realised within the period permitted by the Reserve Bank of India;

(ii) an application fee equivalent to 1% of the FOB value of exports or one thousand rupees whichever is less, shall be payable for applying for grant of extension by the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

(5) Where sale proceeds are not realised by an exporter within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), but such non-realisation of sale proceeds is compensated by the Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. under an insurance cover and the Reserve Bank of India writes off the requirement of realisation of sale proceeds on merits and the exporter produces a certificate from the concerned Foreign Mission of India about the fact of non-recovery of sale proceeds from the buyer, the amount of drawback paid to the exporter or the claimant shall not be recovered.

**19. Power to relax.** - If the Central Government is satisfied that in relation to the export of any goods, the exporter or his authorised agent has, for reasons beyond his control, failed to comply with any of the provisions of these rules, and has thus been entitled to drawback, it may, after considering the representation, if any, made by such exporter or agent, and for reasons to be recorded in writing, exempt such exporter or agent from the provisions of such rule and allow drawback in respect of such goods.

**20. Repeal and saving.** -

(1) From the commencement of these rules, the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995 shall cease to operate.

(2) Notwithstanding such cesser of operation -

- (a) every application made by a manufacturer or an exporter for the determination or revision of the amount or rate of drawback in respect of goods exported before the commencement of these rules but not disposed of before such commencement shall be disposed of in accordance with the provisions of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995 as if these rules had not been made;
- (b) any claim made by an exporter or his authorised agent for the payment of drawback in respect of goods exported before the commencement of these rules but not disposed of before such commencement shall be disposed of in accordance with the provisions of the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995 as if these rules had not been made;

every amount or rate of drawback determined under the Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995 and in force immediately before the commencement of these rules shall cease to operate in respect of goods exported on or after commencement of these rules.

[F. No. 609/75/2017-DBK]

ANAND KUMAR JHA, Under Secy.

**ANNEXURE-I**

**FORM FOR CLAIM OF DRAWBACK UNDER RULE 12**

Original  
Duplicate  
Triplicate  
Quadruplicate

**PART-I**

Ref. Dbk.  
Invoice No.  
Dated:

**PARTICULARS OF GOODS TO BE EXPORTED BY PARCEL POST UNDER CLAIM FOR DRAWBACK**

**FORM NO.**

To

The Assistant/Deputy Commissioner of Customs (Drawback)  
Foreign Post Office \_\_\_\_\_.

We, \_\_\_\_\_ propose to export the undermentioned consignment.

Name and Address of the Consignee \_\_\_\_\_.

Sl. No.	Date of Parcels	Gross Weight	Marks/No. of Pcs.	Qty.	FOB Value	Rate of Net Dbk.	Weight	Amount Rs. P.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

1. Certified that goods were not taken into use after the manufacture.
2. Certified that no separate claim for rebate of duty has been made or will be made to the Central Excise Authorities under rule 18 or rule 19 of Central Excise Rules, 2002 and that the Customs and Central Excise duty has been paid on the raw materials used in the manufacture of the goods. We hereby declare that the declaration made herein is true and correct.

*Strike out whatever is not applicable.*

Dated:

Signature

Place:

Name

Official seal of the Exporter

### Part-II

I have examined the above parcels which contain \_\_\_\_\_ detailed above. The parcels have been packed in my presence and sealed by me with lead/wax seal No. \_\_\_\_\_ bearing the following particulars \_\_\_\_\_.

Date:

Signature of the officer who examined and sealed the consignment

Place:

Certified that the above noted parcels were examined, packed and sealed under my supervision.

Date:

Signature of Supdt. Of Customs/Central Excise

Place:

### Part-III

Forwarded alongwith \_\_\_\_\_ parcels to the Superintendent, foreign Post Office, New Delhi.  
Postal receipt No. \_\_\_\_\_.

Post Master

Post Office

Date and Seal of Post Office

### Part-IV

Inspected \_\_\_\_\_ parcels and found the seal intact. Examined \_\_\_\_\_ parcels where the seals were not found intact.

Pass for export  
Please detain for further action

Date:

Signature of Examiner/Inspector

Place:

Post Appraising Department

Seal of Office

\_\_\_\_\_  
(Place)**Part-V**

Certified that the parcels detailed herein have been exported out of India on \_\_\_\_\_ by \_\_\_\_\_ Air/Sea Ex. S.S. \_\_\_\_\_. Forwarded to the Commissioner/Principal Commissioner of Customs \_\_\_\_\_.

Date:

Signature of Superintendent

Place:

Foreign Post Office

**ANNEXURE-II****APPLICATION FOR SUPPLEMENTARY CLAIM FOR DRAWBACK UNDER RULE 16**

(Where the drawback received falls short of the rate finally fixed by the Government, application for supplementary claim of drawback should be made in the following form)

To

The Assistant/Deputy Commissioner of Customs-in-charge  
Drawback Department

We hereby make a supplementary claim for drawback of Customs/Central Excise which has been less paid to us as explained therein.

1. Exporter
  - (a) Name
  - (b) Address
  - (c) Telephone No.
  - (d) Name of Clearing Agent
2. Goods Exported
  - (a) Description
  - (b) Quantity
    - (i) Gross
    - (ii) Net
  - (c) Marks & No.
  - (d) Destination
  - (e) Shipping Bill No. & Date
3. Vessel
  - (a) Name
  - (b) Rotation No.
4. Drawback already paid
  - (a) Amount
  - (b) Custom House Reference No.
  - (c) Quantity/Value on which allowed
  - (d) Rate at which allowed



5. Drawback not claimed
  - (a) Amount
  - (b) Quantity/Value on which allowed
  - (c) Rate at which claimed
6. Reason for the supplementary claim.
7. No. of documents enclosed\*

#### DECLARATION

1. I/We hereby declare that the supplementary claim of drawback is based on the Customs and Central Excise duties paid on the raw materials used in the manufacture of goods exported and that the duties so paid have not been claimed as rebate under the Central Excise Rules, 2002.
2. I/We hereby declare that the declaration made herein is true and correct.

Signature

Designation

\* Please enclose copy of communication regarding rate of drawback determined under rule 6 or 7, any other document in support of supplementary claim, or other documents as may be prescribed by Principal Commissioner/Commissioner of Customs. Please also enclose calculation sheet.